

खबर संक्षेप

सिकलसेल के खिलाफ एकजुट हुआ समाज



दिशा वेलफेयर और रिलायंस फाउंडेशन की बड़ी पहल शहडोल। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर शनिवार को लालपुर में मानवता और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। दिशा वेलफेयर एसोसिएशन एवं रिलायंस फाउंडेशन के साझा प्रयास से थैलेसीमिया व सिकलसेल जागरूकता कार्यशाला एवं विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के हर वर्ग ने संकल्प लिया कि वे शहडोल को इन अनुशासिक बीमारियों के अभिशाप से मुक्त कराकर ही दम लेंगे।

मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सुधा नामदेव ने कड़े शब्दों में कहा कि जागरूकता के अभाव में हम अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने नियमित रक्तदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताते हुए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। रिलायंस फाउंडेशन के प्रमुख राजीव श्रीवास्तव ने अभियान के लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब तक समाज का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, तब तक इस बीमारी की चेन को तोड़ना नामुमकिन है।

कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक पल वह था, जब थैलेसीमिया योद्धा प्रिया विश्वकर्मा ने अपनी कहानी साझा की। सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा चुकी प्रिया ने बताया कि सही इलाज और समाज के सहयोग से इस जंग को जीता जा सकता है। उनकी सफलता देख वहां मौजूद थैलेसीमिया पीड़ित परिवारों की आंखों में उम्मीद की नई किरण दिखाई दी।

शिविर में एनएसएस के छात्र-छात्राओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और फुटबॉल कोच ने बढ़-चढ़कर रक्तदान किया। दिशा वेलफेयर की अध्यक्ष राूपाली सिंघई ने थैलेसीमिया मुक्त शहडोल का नारा बुलंद करते हुए लोगों को जांच कराने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. नितिन सिंघई ने किया। इस मौके पर डॉ. शमीम अहमद, डॉ. करुणा, सरपंच रामकली बैगा और ब्लड सेंटर की टीम ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। लालपुर से उठी जागरूकता की यह गूँज अब पूरी जिले में बदलाव का सबब बन गई।

खरीफ फसलों की बोनी के लिए प्रदेश में खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध

शहडोल। खरीफ फसलों की बोनी की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 6.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 3.56 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 5.13 लाख मीट्रिक टन डीएपी एवं एनपीके तथा 3.50 लाख मीट्रिक टन एसएसपी खाद का स्टॉक उपलब्ध है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत सरकार द्वारा प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा रही है तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खाद का वितरण लगातार जारी है। किसानों को सोसायटीवार, मार्केट के डबल लॉक केंद्रों, निजी दुकानों एवं ई-विकास पोर्टल के माध्यम से खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार खाद की बुकिंग ई-विकास पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं तथा अपनी सुविधा के अनुसार खाद प्राप्त कर सकते हैं। ई-विकास प्रणाली में राजस्व पट्टाधारी, वन पट्टाधारी, सिकमी किसान, शारीरिक रूप से अक्षम किसान, वृद्ध किसान, मृतक किसान के वारिसों एवं धार्मिक संस्थानों/ट्रस्ट की भूमि के लिए भी खाद उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खरीफ फसलों की बोनी के लिए अनुशंसित मात्रा के अनुसार यूरिया, एसएसपी, डीएपी एवं पोटाश खाद का उपयोग करें।

रामपुर बटुरा ओसीएम में फूटा मजदूरों के सब्र का बांध

जय अम्बे कंपनी के खिलाफ आर-पार की जंग!

मजदूरों ने ठप्प किया कोयले का चक्का

एचपीसी वेतनमान की मांग को लेकर गेट पर जमाया डेरा, प्रबंधन के हाथ-पांव फूले

शहडोल। कोयले की काली कालिख से उजाला पैदा करने वाले मजदूरों के पसीने की कीमत पर जब धोखाधड़ी का ग्रहण लगा, तो सब्र का बांध टूट गया। जिले के अमलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल सोहागपुर एरिया की रामपुर बटुरा ओसीएम में उस वक्त ज्वालामुखी फट पड़ा, जब निजी ठेका कंपनी जय अम्बे के सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एचपीसी (हाई पावर कमेटी) वेतनमान लागू न करने और कोडिडों के भाव मजदूरी कराने से नाराज मजदूरों ने खदान का कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया है। फिलहाल, खदान के गेट पर मजदूरों का हुजूम इंकलाब के नारे बुलंद कर रहा है और कंपनी का प्रबंधन हिल गया है।

वेतन विसंगति का खेल

रामपुर बटुरा ओसीएम में कोयला और ओबी (ओवरबर्डन) उत्खनन के काम में लगे कुशल और अकुशल श्रमिकों का आरोप है कि जय अम्बे कंपनी ने उन्हें बहुआ मजदूर समझ रखा है। मजदूरों ने दो टुक कहा कि केंद्र सरकार और हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतनमान को ताक पर रखकर कंपनी अपनी जेबें भर रही है। नियमों के मुताबिक जो वेतन मिलना चाहिए, उसका आधा हिस्सा भी मजदूरों के हाथों में नहीं पहुंच रहा है। आंदोलनकारी मजदूरों ने तोखे स्वर में कहा हम जान जोखिम में डालकर खदान की गहराइयों में उतरते हैं ताकि कंपनी मुनाफा कमाए, लेकिन जब हक की बात आती है तो प्रबंधन नियमों का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेता है। अब यह तानाशाही नहीं चलेंगी।

कामकाज पूरी तरह ठप्प, प्रबंधन में हड़कण

जैसे ही आंदोलन की चिंगारी भड़की, खदान के भीतर मशीनों की गड़गड़ाहट शांत हो गई और मजदूरों का शोर



गूंजने लगा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी के मुख्य गेट पर एकत्र हो गए और धरना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए काम बंद आंदोलन से कंपनी प्रबंधन के हाथ-पांव फूल गए हैं। करोड़ों रुपये के उत्खनन कार्य पर ब्रेक लग गया है। अमलाई पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी मौके की नजाकत को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। एसईसीएल प्रबंधन ने फिलहाल इस मामले से दूरी बना रखी है, लेकिन अंदरखाने यह चर्चा तेज है कि यदि यह गतिरोध लंबा खिंचा तो सोहागपुर एरिया के उत्पादन लक्ष्य को बड़ा झटका लग सकता है।

हक नहीं तो काम नहीं

प्रदर्शनकारियों ने हुंकार भरते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई सांकेतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि आर-पार की लड़ाई है। मजदूरों की मांगें बिल्कुल साफ हैं कि एचपीसी वेतनमान तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। पिछले महीनों का बकाया एरियर (वेतन अंतर) तुरंत भुगतान हो। श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधाओं में की जा रही कटौती बंद हो। मजदूर



नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रबंधन लिखित में ठोस आश्वासन नहीं देता और बैंक खातों में बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिखता, तब तक खदान का एक भी चक्का नहीं घूमेगा।

प्रबंधन की चुप्पी बढ़ रही आक्रोश

हरानी की बात यह है कि इतना बड़ा बवाल होने के बावजूद जय अम्बे कंपनी का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मोड़िया के सामने आकर अपना पक्ष रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। प्रबंधन की यह चुप्पी मजदूरों की आग में घी डालने का काम कर रही है। सूत्र बताते हैं कि कंपनी अब पदों के पीछे से आंदोलन को कुचलने या कुछ नेताओं को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार आम मजदूर लामबंद है।

प्रशासन की पैनी नजर

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। अमलाई थाना पुलिस बल मौके पर तैनात है ताकि कानून-व्यवस्था न बिगड़े। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक निजी ठेका कंपनियां सरकारी नियमों को टेंगा दिखाकर मजदूरों का शोषण करती रहेंगी? क्या एसईसीएल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है। अब देखना होगा कि जय अम्बे कंपनी झुकती है या फिर यह आंदोलन शहडोल की धरती पर किसी बड़े श्रमिक विद्रोह का रूप लेता है। फिलहाल, रामपुर बटुरा का माहौल गर्म है और मजदूरों के तैयार बता रहे हैं कि वे इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं।

कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, समन्वय समिति की बैठक में रणभेरी

जिला प्रमारी की मौजूदगी में मिशन संगठन पर मंथन

शहडोल। जिले में सुस्त पड़े विपक्षी खेमे में अब नई ऊर्जा फूटने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समन्वय समिति और विधानसभावार बैठकों में पार्टी ने अपनी आक्रामक रणनीति का खुलासा कर दिया है। जिला प्रमारी और विधायक नारायण पट्टा की मौजूदगी में आयोजित इस महामंथन में साफ संदेश दिया गया है कि अब पार्टी केवल दफ्तरों में नहीं, बल्कि सीधे जनता के बीच और बूथ स्तर पर अपनी ताकत दिखाएगी। मुख्य अतिथि विधायक नारायण पट्टा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। उन्होंने साफ तहज्जे में हिदायत दी कि संगठन की मजबूती के लिए हर पदाधिकारी को अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, बूथ कमेटीयों को लोहे की तरह मजबूत करें और आम जनता की समस्याओं को अपनी आवाज बनाएं।

अध्यक्षीय उद्घोषण में जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि संगठन में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की असली ताकत उसका आपसी समन्वय है। आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत हितों को छोड़कर पार्टी की रीति-नीति को जन-जन तक पहुंचाने में जुट जाएं। बैठक के बाद जयसिंहनगर प्रमारी आशीष त्रिपाठी, जैतपुर प्रमारी मनोज सरफ और ब्यौहारी प्रमारी त्रिभुवन सिंह ने



अलग-अलग मोर्चों पर कमान संभाली। तीनों प्रमारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की जमीनी हकीकत जानी और आगामी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। सदस्यता अभियान से लेकर बूथ प्रबंधन तंत्र के लिए समन्वय बनाया कर दी गई है।

बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जयसवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश कटारें सहित जिले भर के कद्दावर नेता मौजूद रहे। मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला ने जानकारी दी कि पूरी पार्टी अब एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सताक्ष को घेरने की रणनीति पर मुहर लग चुकी है। बैठक के समापन पर जिले भर से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब देखना यह है कि समन्वय की यह नई चाहनी आगामी चुनौतों में कांग्रेस के लिए कितनी मीठी साबित होती है।

जनगणना के जंग में प्रगाणक प्रदीप विश्वकर्मा अक्ल

सीएमओ ने कार्यस्थल पर पहुंचकर किया सम्मान



शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के कड़े निर्देशन और जिला जनगणना अधिकारी सर्वोदय सिंह के मार्गदर्शन में शहडोल नगरपालिका ने जनगणना के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शहरी क्षेत्र में संचालित प्रथम चरण के इस महा-अभियान में उत्कृष्ट विद्यालय रघुराज क्रमांक-2 के प्रगाणक प्रदीप विश्वकर्मा ने अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाते हुए जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

शुक्रवार को नगरपालिका सीएमओ एवं चार्ज अधिकारी श्रीमती आशा जितेंद्र भंडारी ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (वार्ड 25) स्थित कार्यस्थल पर पहुंचकर प्रदीप विश्वकर्मा को पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनके समर्पण की सराहना की। सीएमओ ने दो टुक शब्दों में कहा कि जनगणना शासन की रीढ़ है और इसमें लापरवाही की कोई जगह नहीं है। उन्होंने अन्य प्रगाणकों को सीखाह देते हुए प्रदीप की तरह पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम पूरा करने का आह्वान किया।

इस दौरान पर्यवेशक रेखा मिश्रा, मंजू ओझा, वार्ड प्रभारी भोला सिंह और मनीष श्रीवास्तव सहित पूरी टीम मौजूद रही। नगरपालिका की इस त्वरित सराहना के जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों में नया उत्साह देखा जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी फील्ड पर पसीना बहाकर सटीक डेटा जुटाएंगे, उन्हें शासन स्तर पर भी पुरस्कृत किया जाएगा।

न्यायालय में जर्जर लिंटर और गिरते प्लास्टर से वकीलों में दहशत

शहडोल।

जिला न्यायालय परिसर इन दिनों न्याय काम और हादसों का केंद्र बन गया है। शुक्रवार दोपहर न्यायालय का मुख्य प्रवेश द्वार अचानक दहल उठा, जब पोच का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि इस खौफनाक मंजर से कुछ सेकंड पहले ही वहां मौजूद अधिवक्ता हट चुके थे, वरना न्याय के मंदिर में ही लार्शे बिछ जातीं। हालांकि, मलबे की चपेट में आने से कई अधिवक्ताओं के वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिस जगह यह हादसा हुआ, वहीं से जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सीजेएम न्यायालय का रास्ता गुजरता है। घटना के बाद सीजेएम शहडोल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त स्थान को बंद करवाया और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को मौके पर तलब किया। निरीक्षण में साफ हो गया कि पूरी बिल्डिंग कंडम घोषित होने की कगार पर है और कभी भी कोई बड़ा लिंटर किसी मासूम नागरिक या अधिवक्ता के लिए काल बन सकता है।यह पहली बार नहीं है जब मौत ने यहां दस्तक दी है। पूर्व में अधिवक्ता अभय त्रिपाठी के ऊपर लिंटर गिरने से वे गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। कई कर्मचारी भी बाल-बाल बचे हैं। बार-बार जिला न्यायाधीश को चेताने के बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि क्या विभाग को किसी बड़ी जनहानि का इंतजार है। न्यायालय में आने वाले हजारों पक्षकारों और सैकड़ों वकीलों की जान जोखिम में डालकर यहां काम संचालित किया जा रहा है। जर्जर हो चुकी इस मौत की इमारत का तत्काल तकनीकी परीक्षण और पूर्ण मरम्मत अनिवार्य है। अगर वक्त रहते प्रशासन नहीं जागा, तो भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और संबंधित अधिकारियों की होगी।



जमीन पर काम दिखाओ, बहानेबाजी नहीं: शुवल ब्यौहारी जनपद के सामने से हटेगी शराब दुकान

जर्जर स्कूलों की मरम्मत और अंधूरे पुलों पर प्रभारी मंत्री का अल्टीमेटम

शहडोल। उप-मुख्यमंत्री और जिले के प्रमारी मंत्री राजेंद्र शुवल ने जिले की विकास योजनाओं में कानूआ चाल चलने वाले विभागीय अफसरों को दो-टुक चेतावनी दे दी है। बाणसागर सिकट हाउस में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में डिप्टी सीधम का रोढ़ रूप देखने को मिला। उन्होंने साफ कहा कि कागजों पर विकास की लफ्फाजी बंद करें और स्वीकृत कार्यों की जमीन पर उतारें। बैठक में उप-मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विजयसोता पुल और उमरिया मार्ग पर बरसे मंत्री

बैठक के दौरान उप-मुख्यमंत्री ने शहडोल-उमरिया मार्ग और ब्यौहारी के विजयसोता पुल के निर्माण में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता की सुविधा से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स में अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि हर समय-सीमा बैठक में इन कार्यों की अतिवार्थ समीक्षा की जाए। मन्त्री सिंघाई परियोजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी।

ब्यौहारी शराब दुकान हटाने का फरमान

आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उप-मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत कार्यालय ब्यौहारी के ठीक सामने संचालित शराब दुकान को तत्काल वहां से हटाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों और जनहित के स्थानों के पास ऐसी दुकानों का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद से क्षेत्र की जनता में हर्ष है, वहीं शराब माफिया और लापरवाह आबकारी अमले में हड़कण मच गया है।

जर्जर स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक

जिले की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर रुख अपनाते हुए श्री

एनएसएस ने शुरू

किया शकोरा अभियान

प्यासे परिंदों के लिए वाटिका में सजाए मिट्टी के पात्र



शहडोल। ग्रीष्म गर्मी और आसमान से बरसती आग के बीच जब इंसानों का हाल बेहाल है, तो बेजुबान पक्षियों की पीड़ा को समझते हुए पंडित शंभूनाथ शुवल विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश की है। विश्वविद्यालय परिसर की वाटिका में शनिवार को शकोरा अभियान के तहत पेड़ों पर मिट्टी के बर्तन (शकोरे) बांधे गए और उनमें शीतल जल भरा गया, ताकि प्यास से तड़पते परिंदों को राहत मिल सके।

इस पुनीत कार्य में परिसर प्रभारी प्रोफेसर गीता सराफ ने स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि गर्मी में पानी की कमी से हजारों पक्षी दम तोड़ देते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास कई जिंदगियां बचा सकता है। उन्होंने जन-जन से अपील की कि वे अपने घरों और छतों पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें।

एनएसएस प्रभारी डॉ. धानी जामोद के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने न केवल शकोरे लगाए, बल्कि उनकी नियमित साफ-सफाई और पानी भरने की जिम्मेदारी भी ली। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनीता बाथरे, डॉ. सुषमा नेताम, डॉ. दिनेश मिश्र, डॉ. सागर पांडेय, डॉ. अंबिकेश नामदेव और डॉ. वीरेंद्र कुर्मी सहित लखेश्वर, ऋषभ व संस्कार जैसे छात्र सैनिकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय की इस पहल ने समाज को यह संदेश दिया है कि विकास के साथ-साथ प्रकृति और उसके जीवों का संरक्षण ही सच्ची मानवता है। अब उम्मीद है कि यह अभियान एक जनआंदोलन बनेगा और शहर का हर नागरिक इस गर्मी में पक्षियों का दोस्त बनकर उभरेगा।



अनुशासन और उपस्थिति में कोई समझौता नहीं होगा।

यह प्रशिक्षण वर्ग केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि 38 घंटे का एक गहन बौद्धिक सत्र होगा। जिला संयोजक राकेश पांडे के अनुसार, इन दो दिनों में कुल 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। जिसमें प्रथम दिन 5 और दूसरे दिन 6 सत्र होंगे। प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, विचार परिवार, बूथ प्रबंधन, मन की बात का प्रभाव और देश के समक्ष वर्तमान राजनीतिक चुनौतियां। शिविर के दौरान कार्यक्रमताओं को योग-व्यायाम से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक के कड़े प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

प्रशिक्षण वर्ग के साथ-साथ जिले की

राजनीतिक तपिश भी बढ़ गई है। बाणसागर रेस्ट हाउस में उपमुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुवल की मौजूदगी में भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। इसमें सांसद राजेश मिश्रा, सभांग प्रभारी गौरव सिरोंठिया और विधायकों की उपस्थिति में संगठन की मजबूती पर गहन चर्चा की गई। 16 मई को उद्घाटन सत्र के साथ शुरू होने वाले इस वर्ग में प्रदेश स्तर के कई कद्दावर नेता और प्रशिक्षक अपना मार्गदर्शन देंगे। भाजपा के इस कड़े प्रशिक्षण वर्ग से साफ संदेश मिल रहा है कि संगठन अब बूथ स्तर पर किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। अनुशासन की चादर और जीत के संकल्प के साथ शहडोल भाजपा की यह नई फौज मैदान में उतरने को तैयार है।



शुवल ने निर्देश दिए कि जिले के जितने भी शासकीय विद्यालय जर्जर अवस्था में हैं, उन्हें तुरंत बंदिस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की जान जोखिम में डालकर शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसलिए मरम्मत का काम प्राथमिकता पर हो। साथ ही, मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज और निर्माणधीन हेल्थ सेंटरों को जल्द से जल्द पूरा कर लोकार्पण की स्थिति में लाने के निर्देश दिए।

भर्ती और रेल लाइन कार्यों की भी ली खबर

डिप्टी सीएम ने केवल सड़क और पुल ही नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों की भर्ती, जयसिंहनगर बाईपास, और कटनी-सिंगरौली डबल रेलवे लाइन के कार्यों का भी पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाला। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सांदीपनि विद्यालय की समय पर पूर्ण करने का दबाव बनाया।

बैठक में दिग्गजों की मौजूदगी

इस हाई-प्रोफाइल बैठक में सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक जयसिंह मराठी, शरद कोल, मन्नीषा सिंह सहित कलेक्टर डॉ. केदार सिंह और जिला पंचायत सीईओ शिवम प्रजापति मौजूद रहे। प्रमारी मंत्री के कड़े तैयारी ने यह साफ कर दिया है कि अब शहडोल के विकास की फाहलें धूल नहीं फाँकेगी, बल्कि उन्हें रफ्तार पकड़नी ही होगी।



खबर संक्षेप

जिला प्रभारी मंत्री का
भ्रमण कार्यक्रम आज

उमरिया। प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री नागर सिंह चौहान एक दिवसीय भ्रमण पर 9 मई को ताला आएंगे। श्री चौहान कार द्वारा भोपाल से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे फारेस्ट रेस्ट हाउस ताला आएंगे। दोपहर 12.30 बजे जिला अधिकारियों की बैठक फारेस्ट रेस्ट हाउस में लेंगे। दोपहर 1.30 बजे जिला कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के पश्चात सायं 4 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

कलेक्टर ने ग्राम सेहरा में
प्रगणक द्वारा किए जा रहे
मकान सूचीकरण कार्य का
किया अवलोकन



उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम सेहरा पहुंचकर प्रगणक मीना सिंह द्वारा दूधना पाल एवं तुलई पाल का किए जा रहे मकान सूचीकरण का एचएलओ ऐप के माध्यम से अपने समक्ष उद्घी करवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की जानकारी ली तथा प्रगणकों से विधार्थित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती सहाय ने प्रगणकों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी,पारदर्शिता एवं शुद्धता के साथ किया जाए, ताकि शासन को सही एवं अद्यतन आंकड़े प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी चर्चा की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें, ताकि जिले का सही आंकलन हो सके। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अमर सिंह, एसडीएम मानपुर हरजीत कौर कलसी,जनपद सीईओ मानपुर अंकित सिरोटिया सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने कारीतलाई में
विष्णु वराह का किया
अवलोकन

कटनी। कलेक्टर आशीष तिवारी ने गुरुवार को विजयराघवगढ़ तहसील के कारीतलाई पहुंचकर भगवान विष्णु के वराह अवतार की मध्य प्रतिमा का अवलोकन कर प्रतिमा की पूजा-अर्चना कर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिमा की कलात्मकता, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर श्री तिवारी ने कहा कि इस प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर हमारी समृद्ध परंपरा और आस्था का प्रतीक हैं। उन्होंने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित एवं विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अवलोकन के दौरान जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, सहायक कलेक्टर श्लोक वाढकर तथा एसडीएम विवेक गुप्ता भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कलेक्टर श्री तिवारी से प्रतिमा परिसर की व्यवस्थाओं और स्थानीय महत्व के संबंध में जानकारी साझा की

प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु अनूपपुर में ‘ज्ञान भारतम मिशन’ प्रारंभ

अनूपपुर जिले के नागरिकों से
सहयोग की गई अपील

अनूपपुर। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की प्राचीन हस्तलिखित विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से ‘ज्ञान भारतम मिशन’ प्रारंभ किया गया है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैज्ञानिक महत्व की प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण तथा डिजिटलीकरण किया जाएगा। जिले में मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा स्थानीय नागरिकों एवं

संस्थाओं से सहयोग की अपील की गई है। संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल के निर्देशानुसार जिले में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा निजी शोध संस्थानों, महाविद्यालयों, प्राचीन ग्रंथालयों, मंदिरों, मठों, आश्रमों तथा निजी ट्रस्टों में संरक्षित हस्तलिखित पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से 75 वर्ष अथवा उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियों की जानकारी संकलित की जाएगी। संग्रहित जानकारी को ‘ज्ञान भारतम ऐप’ के माध्यम से डिजिटल स्वरूप में अपलोड किया जाएगा, जिससे जिले की अमूल्य सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर सुरक्षित रह सकेगी। यह पहल भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के साथ-

साथ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिले के समस्त नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि यदि उनके पास अथवा उनके संज्ञान में किसी संस्था के पास प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां उपलब्ध हों, तो उनकी जानकारी साझा कर इस राष्ट्रव्यापी अभियान में सहभागिता सुनिश्चित करें। यह पांडुलिपियां हमारे पूर्वजों के ज्ञान, शोध एवं वैज्ञानिक टिकोण की अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण समय की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थाएं 25 मई तक जिला स्तरीय समिति के नोडल अधिकारी के मोबाइल नंबर 7000389451 पर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण की आगामी कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

मकानसूचीकरण कार्य का जनगणना नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण



उमरिया। नगर पालिका परिषद उमरिया क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान प्रगणकों द्वारा किए जा रहे कार्य का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि वे जनगणना

कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि सही एवं सटीक जानकारी संकलित की जा सके। निरीक्षण के दौरान प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा गया कि जनगणना का कार्य शासन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। जिले में मकानसूचीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक कुल 1412 एचएलबी में से 53 एचएलबी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा शेष कार्य भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।इस अवसर पर जनगणना नोडल अधिकारी प्रत्युष श्रीवास्तव,मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा,फील्ड ट्रेनर प्रियंक अग्रवाल उपस्थित रहे।



सहायक प्रबंधक की गुंडागर्दी और मुआवजे के खूनी खेल ने रोका कोयले का चक्का!

एसईसीएल की काली करतूतों पर भड़का आदिवासियों का सैलाब

शहडोल। शहडोल की कोख से करोड़ों का काला सोना लूटने वाला एसईसीएल प्रबंधन अब आदिवासियों के सब्र की परीक्षा ले रहा है। रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट में अपनी पुश्तैनी जमीन गंवा चुके डोंगरी टोला के आदिवासी किसानों ने प्रबंधन के धोखे के साम्राज्य के खिलाफ अंतिम युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। खदान की धधकती आग से ज्यादा तेज गुस्सा आज उन किसानों की आंखों में है, जिनकी जमीन पर खड़ी होकर जय अम्बे जैसी निजी कंपनियां अरबों का मुनाफा कूट रही हैं, जबकि असली मालिक सड़कों पर मौत या हक के नारे लगा रहे हैं।

सत्ता की हनक में चूर सहायक
प्रबंधक

प्रबंधन की बौखलाहट का आलम यह है कि भ्रष्टाचार की खबरें बाहर आने से रोकने के लिए अधिकारी अब तानाशाही पर उतर आए हैं। आंदोलन का सच दिखाने पहुंचे पत्रकारों से सहायक खान प्रबंधक अर्जुन जोड़े ने न केवल सरेंआम हुज्जतबाजी की, बल्कि अपनी पद की गरिमा को ताक पर रखकर कवरज रोकने के



लिए गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। साहब शायद यह भूल गए कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की आवाज दबाने का अंजाम क्या होता है। बदसलूकी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जो चीख-चीख कर कह रहा है कि खदान के भीतर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।

बाहरी लोगों को मलाई, भूमिपुत्रों
को केवल धूल!

आरोप है कि जय अम्बे कंपनी ने स्थानीय

आदिवासियों के हक पर डकैती डाली है। किसानों की उपजाऊ जमीन छीनकर वहां मशीनों का शोर तो गूंज रहा है, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के नाम पर प्रबंधन की सांप सूंघ जाता है।बुद्ध और मुन्ने लाल बैगा जैसे किसानों का कहना है कि हमारी छाती पर पैर रखकर बाहरी लोगों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। यह उपेक्षा अब विद्रोह की चिंगारी बन चुकी है, जिसने आज खदान के पहिए जाम कर दिए हैं।एसईसीएल ने न केवल जमीन छीनी, बल्कि वादों की अर्थी भी निकाल दी। दर्जनों किसानों की मॉनेटरी जॉब



फाइलों में दफन है। नबंदा और हरिलाल जैसे आदिवासी आज भी मुआवजे की एक-एक बच्चे खदान के मुहाने पर बैठे हैं। प्रशासन और भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद आदिवासियों का एक ही नारा है, जमीन हमारी है, कोयला हमारा है, तो उस पर हक भी हमारा होगा! सवाल यह है कि करोड़ों का नुकसान होने पर चीखने वाला प्रशासन तब कहां सो जाता है जब आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोंटा जाता है।

जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। भीषण गर्मी में बुजुर्ग महिलाएं और मासूम बच्चे खदान के मुहाने पर बैठे हैं। प्रशासन और भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद आदिवासियों का एक ही नारा है, जमीन हमारी है, कोयला हमारा है, तो उस पर हक भी हमारा होगा! सवाल यह है कि करोड़ों का नुकसान होने पर चीखने वाला प्रशासन तब कहां सो जाता है जब आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोंटा जाता है।

करो या मरो का संकल्प

आंदोलन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है

नहीं हुई नहर की सफाई, किसान
अपने पैसे से करा रहे मरम्मत

मामला पिपरिया जलाशय नहर का,
अन्नदाता हो रहे परेशान, 4 वर्षों से
नहीं हो रही मरम्मत

कोतमा। जल संरक्षण एवं किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा करोड़ों की लागत से बांध और नहरों का निर्माण कराया गया है। गत वर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा बैठकों में जलाशयों की मरम्मत और नहर निर्माण में गुणवत्ता के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे। मौके पर अधिकारियों ने हामी भरी किंतु नतीजा दाक के तीन पात ही निकला। अधिकांश जलाशयों की जमीनी हकीकत यह है कि इन कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। कागजों में चुरस्त-दुरुस्त व्यवस्था हकीकत से कोसों दूर है जिसका खामियाजा अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला कोतमा तहसील के पिपरिया जलाशय का भी है। जहां 10 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय एवं नहर का निर्माण कार्य कराया गया। कार्य पूरा होना शेष ही है, वही जुलाई 2022 में पहली ही बारिश में नहर का अधिकांश हिस्सा जगह-जगह से टूट गया था। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों ने शिकायत की। सुनवाई नहीं होने पर मामला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा जहां से मरम्मत के लिए निर्देशित किया गया था। औपचारिकत के लिए टूटी हुई नहर में मिट्टी डाली गई और उसके बाद से दोबारा अधिकारी पहुंचे ही नहीं। पिपरिया-जोगीटोला में 26 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय एवं लगभग 8 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, 16 करोड़ रुपए भू अर्जन एवं 10 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में व्यय होने हैं। जलाशय का कार्य प्रगति पर है जबकि नहर निर्माण का कार्य कागजों में पूरा कर लिया गया है। इस जलाशय से 845 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2021 में कार्य को पूरा हो जाना था किंतु जलाशय निर्माण के साथ ही जोगी टोला ग्राम जाने वाली सड़क के विकल्प के लिए यह कार्य अंत तक पूरा नहीं हो पाया है। जलाशय से निकलने वाली नहर देवगांव ग्राम में लखन यादव के घर के समीप टूट गई थी। बीते वर्ष जुलाई महीने में नहर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके बाद से पानी नहर के माध्यम से बेकार ही बह जाता है। जिसकी मरम्मत आज तक नहीं करवाया गया। देवगांव, डोंगरीटोला, चटहटोला मनटोलिया तथा धुम्मा ग्राम के 5 सैकड़ से ज्यादा किसान नहर टूटने की वजह से परेशान हैं। जोगी टोला गांव के पास दुर्गेश सिंह पिता रोहणी सिंह के खेत के पास भी नहर विगत एक साल से टूटा हुआ है जिसके मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं



करवाया गया। गत वर्ष कम बारिश की वजह से खेतों में जलभराव नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से धान की रोपाई भी प्रभावित हो रही थी। गेहूं की फसल को भी सिंचाई का लाभ नहीं मिल पाया है। जिससे फसल बर्बाद हो चुके हैं, पूर्व में किसानों के द्वारा इस मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई थी। हर वर्ष बारिश से पूर्व किसानों के द्वारा नहर की मरम्मत की मांग की जाती रही है। जिसको लेकर सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। वर्ष 2023 में जून महीने के आखिरी पखवाड़े में नहर की मरम्मत और निरीक्षण के लिए जल संसाधन का अमला मौके पर पहुंचा। टूटी हुई नहर के दो हिस्सों में मिट्टी का भरवा किया गया, एक दो जगह पर मिट्टी डाली गई और उसके बाद शेष नहर की मरम्मत के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। जगह-जगह से टूट चुकी नहर की मरम्मत नहीं होने के कारण जलाशय से आने वाला पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है। पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार शिकायत करते हुए पत्राचार भी किया जा रहा है, नतीजा सिफर ही रहा है। कोतमा सब डिवीजन के बाकी जलाशय के ग्राम छिडीमिडी के किसानों के द्वारा शिकायत किया गया है कि नहर टूटने के कारण रवि फसल की खेती नहीं कर पाये जबकि नहर मरम्मत को लेकर बार बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता है। लामटोला जलाशय के डेन के नीचे ही नहर टूटने के कारण पानी किसानों के खेतों में नहीं पहुंच पा रहा है और पानी नाले में चला जाता है जिसके कारण किसानों को समय पर पानी नहीं मिलने के कारण खेती करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

धान की सीधी बुवाई तकनीक से बदली किसान तारन सिंह की तकदीर

अनूपपुर। जिला अनूपपुर के विकासखंड कोतमा अंतर्गत ग्राम डोंगरियाकला के प्रगतिशील किसान तारन सिंह ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। वे वर्षों से पारंपरिक रोपाई विधि से धान की खेती करते थे, जिसमें अधिक लागत, समय तथा मजदूरों की समस्या बनी रहती थी। वर्ष 2024-25 में आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान मेले में उन्होंने धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) तकनीक की जानकारी प्राप्त की और इससे प्रेरित होकर अपने खेत में सीड ड्रिल मशीन द्वारा धान की बुवाई कराई। डीएसआर तकनीक अपनाने से किसान की खेती में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। जहां पारंपरिक रोपाई में प्रति हेक्टेयर लगभग 12 से 15 हजार रुपये तक का खर्च आता था, वहीं सीधी बुवाई में यह लागत बहुत कम होकर लगभग 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर रह गई। साथ ही समय पर बुवाई होने से फसल का विकास बेहतर हुआ तथा उर्वरकों का समुचित उपयोग भी संभव हो पाया। इस तकनीक के कारण किसान को प्रति हेक्टेयर लगभग 5 किबंटल अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त हुआ तथा कुल मिलाकर लगभग 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त लाभ मिला। धान की फसल समय पर पकने से अब वे उसी खेत में रबी फसल भी आसानी से ले पा रहे हैं, जिससे उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। किसान तारन सिंह की यह सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत है। आधुनिक तकनीक अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाया जा सकता है।



